विकास के लिये हर प्रोग्राम चलाया जायगा तो मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता हू कि जहां कृषि मंडी समितियां हैं उनके विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या इस बात के लिये केन्द्र से कोई अतिरिक्त गेहूं भडार मांगा है या 1 लाख 66 हजार टन में ही सम्मिलित है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मंडियों के विकास का तो प्रश्न नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो मडियां हैं उनके विकास के लिये उनके पास कुछ धन उपलब्ध है । सड़कों को बनाने के लिये कुछ नकद रुपये की जरूरत पड़ती है तो नकदी वाला हिस्सा कृषि मडियां दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, और बाकी जो गल्ले का खर्चा है वह सेव किया जायगा । दोनों स्कीमों को मिलाकर 3,000 किलोमीटर पुख्ता सड़क बनाने का उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव है ।

SHRI C. N. VISVANATHAN: The hon. Minister, in his reply, has mentioned about 12 States, but he has not said anything about Tamil Nadu and Pondicherry. I want to know from the hon. Minister whether Tamil Nadu and Pondicherry will be included and what steps have been taken to implement the programme? What are the reasons for leaving out Tamil Nadu and Pondicherry and what is the quantity they are going to supply to them?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We have written to the Chief Ministers informing them about this new scheme and inviting requests from them. We have made allocations only in respect of those States from which requests have already been received. We will certainly welcome any scheme from Tamil Nadu, but, so far, none has been received.

दिल्ली में तारा-घर की स्थापना

*267. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा पड़ौसी राज्यों के छात्रों एवं लोगों को ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान से अवगत कराने के लिए दिल्ली में तारा-घर बनाने का है;

(ख) यदि हां तो यह तार-घर कब तक स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : जहां तक मैं मंत्री महोदय का उत्तर सुन सका हूं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्या यह ठीक है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जी हां, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को ज्योतिष और खगोल विद्या जानने के लिये इस प्रकार का तारा-घर परमावश्यक है । कलकत्ता और बम्बई से यह सिद्ध हो गया है कि वहां पर करीबन विद्यार्थियों को ही इससे लाभ नहीं हुआ है, बल्कि

साधारण जनता भी उस से बहुत लाभ उठाती है और जितनी उस पर लागत आई है, उस से कई गुना अधिक धन टिकटों के रूप में अब तक आ भी चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लाभ के दृष्टिकोण से ताराघर का यहां होना आवश्यक है और उसकी लागत भी जल्दी ही टिकटों के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी, तो इस तरह का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन क्यों नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अभी तक यह प्रस्ताव नहीं आया है । जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, यह तो सही है, लेकिन इस में रुपये की भी बात आती है, इस में बहुत ज्यादा खर्च होगा ।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की ओर से फिजिक्स, कैमिस्ट्री ब्लाक्स में दिल्ली में एक आब्जरवेटरी टावर बनाने के लिये कोशिश की गई थी और एक टावर बन भी चुका है, लेकिन उस पर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ काम नहीं कर रही है । विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभी आब्जरवेटरी टावर से काम चल सकता है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा था और वह यह कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये ताराघर एक अनिवार्य अंग है । लेकिन आप यहां आब्जरवेटरी टावर बना रहे हैं, और इसका भी इस्तेमाल न होने से ऐसी स्थिति में कोई लाभ नहीं होगा । लेकिन ताराघर बनाने पर साधारण जनता भी उसे देखेगी, उस पर टिकट लगाने से आमदनी भी सरकार को हो सकेगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है, इसका क्या कारण है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अभी तो हम बना नहीं सकते हैं । विद्यार्थी पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, ताराघर तो बहुत दूर की बात है ।

// DR KARAN SINGH: I think, the hon. Education Minister should appreciate that a planetarium is something which is really very very important and it is extra-ordinary that a capital city like ours does not have its own planetarium. We have Nehru Planetarium in Bombay and there is one in Calcutta also. To have observatories and to see the stars through a telescope is a different matter. A planetarium is an absolutely essential thing for education not only of students but also of public. May I, therefore, suggest for consideration of the hon. Minister that if it is not under the University Grants Commission, some other agency should be requested to put up a planetarium here so that we can see the magnificent spectacle of the Heavens as they have been and as they will be in the future.

MR. SPEAKER: I think this is a suggestion for action.

PROF. P G. MAVALANKAR: The hon. Minister comes from Calcutta and he would be aware that the Planetarium at Calcutta is one of the best in the world. May I know from the hon. Minister, whether he would be good enough to have this proposal seriously considered in his Ministry, while he is the Minister, because Delhi is not only the capital city of India, but it is also a good place for study and a central place in the sense that a very large number of people come here from all parts of India and the World. A variety of students also come on study tourist from other States I would like to know what the hon. Minister thinks about this.

Secondly, since it is connected with astronomy and astrology, and a large number of politicians are conncerned with astrology—whether of this Government or of the previous Government —it would be helpful to them, too!

MR. SPEAKER: The second part is more important.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As far as I know, the Planetarium in Calcutta has been constructed through private munificence and some well known industrial house has financed it and is looking after the management. I do not know how the Bombay Planetarium is coming up. Government certainly would not have any objection whatsoever if some private industrialist or some other body comes up for putting up a Planetarium. In that case, if such a proposal comes, I would plead with my esteemed colleague Shri Sikandar Bakht for commissioning of land.

SHRIMATI V. JEYLAKSHMI: Is it a fact that many Planetoriums have been set up in North India but only one has been set up in Vijayawada for the entire south, if so, will the Minister consider establishing Planetoriums in all the State Capitals like Hyderabad, Bangalore, Madras etc. so that students and other people might be educated in the fields of astrology and astronomy?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is no such proposal.

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : अभी मंत्री महोदय से यह बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि जब बच्चों को पढ़ने के लिए पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, तो प्लैनेटेरियम आदि चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं । इस के मानी ये हैं कि जब तक सब बच्चों के लिए स्कूल-भवन नहीं बन जायेंगे, तब तक कोई लैबोरेटरी बनेगी ही नहीं । यदि लैबोरेटरी वगैरह बन सकती हैं, तो प्लैनेटेरियम क्यों नहीं बन सकता है ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: It is always a question of priorities: I have not said that laboratories are not important....

MR. SPEAKER: Question No. 268.

सुपर बाजरों तथा जनता दुकानों के माध्यम से गेहूं तथा चीनी सप्लाई करने का प्रस्ताव

*268. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में गेहूं तथा चीनी क्रमश : 150 रुपए तथा 430 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचे जा रहे हैं , जब कि सरकारी गोदामों में और अधिक भंडारण क्षमता नहीं है चीनी मिलें फिर चालू हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गेहूं तथा चीनी के मूल्य निर्धारित करने तथा इन्हें सुपर बाजरों तथा जनता दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने का है जैसा कि दालों के मामले में किया गया है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 24 नवम्बर, 1977 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों जहां पर अधिकांशत: बढ़िया किस्म के लिए अधिक मूल्य होता है, को छोड़ कर गेहू के थोक मूल्य आम तौर पर 150 रूपये प्रति क्विंटल से कम थे। इसी प्रकार, चीनी के थोक मूल्य भी आम तौर पर 430 रुपये प्रति क्विंटल से कम थे।

(ख) गेहूं और चीनी उचित दर की दुकानों से निर्धारित मूल्य पर दिए जाते हैं जिस में केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को दिए गए गेहूं का भारतीय खाद्य निगम डिपो पर मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल और